आकाशवाणी केन्द्र शिमला
02.09.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18.00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज शिमला में प्रदेश राजपूत कल्याण बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में सरकार ने अनेक योजनाएं बनाकर धरातल पर उतारी हैं। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इस वर्ष 2 अक्तूबर से प्रदेश में मुख्यमंत्री का अपना परिवार सुखी परिवार योजना आरंभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके तहत करीब 2 लाख गरीब परिवारों को 3 सौ यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं को 15 सौ रूपए प्रति माह प्रदान किए जाएंगे।

राज्यपाल

राज्यपाल कविन्द्र गुप्ता ने हमीरपुर में पूर्व सैनिकों से भेंट कर उनके कल्याण व हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जानकारी ली। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व सैनिकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों व समस्याओं को राज्य सरकार के समक्ष उचित कार्रवाई के लिए प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा। राज्यपाल ने हमीरपुर में शहीदी स्मारक के निर्माण के लिए 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की।

प्रश्नकाल–1800

हिमाचल प्रदेश में अवैध खनन और खनन सामग्री के अवैध परिवहन के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। शिमला में चल रहे प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज प्रश्नकाल में विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान इस वर्ष एक अगस्त तक खनन विभाग ने अवैध खनन और परिवहन के कुल 13 हज़ार 82 मामले दर्ज किए हैं। इनमें से 10 हज़ार एक सौ 52 मामलों में दोषियों से जुर्माने के रूप में 8 करोड़ 79 लाख 25 हजार 7 सौ 70 रुपये की राशि वसूल की गई है। उद्योग मंत्री ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न नदी–नालों में कुल 3 सौ 5 खनन पट्टे प्रदान किए गए हैं। इन खनन पट्टों से एक अगस्त 2026 तक सरकार को 3 सौ 2 करोड़ 88 लाख 63 हजार 9 सौ 38 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी के सवाल के जवाब में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने बताया कि कसौली में जायका प्रोजेक्ट के तहत चल रही 6 सिंचाई योजनाओं के काम में कमी पाए जाने पर जांच करवा कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को इन योजनाओं के काम की रिपोर्ट एक सप्ताह के भीतर देने के निर्देश भी दिए हैं।

विधेयक

विधानसभा में आज विपक्षी दल भाजपा के विरोध के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2026 ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि इससे विश्वविद्यालयों की सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पारदर्शिता आएगी। इस संशोधन विधेयक में प्रावधान किया गया है कि विश्वविद्यालयों की वित्त समिति की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के वित्त सचिव करेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति ही कर पाएंगे, अन्य सभी नियुक्तियां लोक सेवा आयोग और चयन आयोग के जरिये होंगी।

बिजली बोर्ड

राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारी, इंजीनियर और पेंशनरों ने ओपीएस बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज शिमला के चौड़ा मैदान में सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर बिजली बोर्ड ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने बोर्ड में 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की सरकार से मांग की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल कर दी थी, लेकिन बिजली बोर्ड के कर्मचारी इससे वंचित हैं। हीरालाल वर्मा ने बिजली बोर्ड में खाली पड़े पदों को भरने की भी सरकार से मांग की।

अनुराग ठाकुर

पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। वे आज उना में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने केंद्र प्रायोजित विभिन्न विकास योजनाओं की गहन समीक्षा भी की। अनुराग ठाकुर ने उपलब्ध धनराशि का समयबद्ध व प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने ए.प.पी लैड के तहत लंबित कार्य 15 अक्तूबर तक पूरा करने को भी कहा। अनुराग ठाकुर ने उना के मलाहत में निर्माणाधीन पी.जी.आई. सेटेलाइट सेंटर के निर्माण कार्य में हो रही देरी में नाराजगी जताई।